Vol III Issue II March 2013
Impact Factor : 0.2105
ISSN No : 2230-7850

Monthly Multidisciplinary
Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-chief
H.N.Jagtap

IMPACT FACTOR : 0.2105

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya [Malaysia]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus Pop

Mohammad Hailat
Dept. of Mathmatical Sciences, University of South Carolina Aiken, Aiken SC 29801

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Department of Chemistry, Lahore University of Management Sciences [PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

Nawab Ali Khan
College of Business Administration

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Indian Streams Research Journal
Volume 3, Issue. 2,March. 2013
ISSN:-2230-7850
Available online at www.isrj.net
ORIGINAL ARTICLE

ग्रामीण उच्च शिक्षा : समस्याएँ एवं समाधान

अशोक मरळे

हिंदी विभाग, यशवंतराव चव्हाण कला व वाणिज्य
महाविद्यालय, इस्लामपुर, तह. वाळवा, जि. सांगली.

सारांशः

आधुनिक युग में व्यवसाय तथा नौकरी के क्षेत्र विसतारित हो रहे हैं। इस कारण उच्च शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। वैश्वीकरण, निजीकरण के साथ–साथ विदेशी तथा अभिमत विश्वविद्यालयों का सामना करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों को कुछ आधुनिक संकल्पनाओं का स्वीकार करते हुए नए कृति कार्यक्रम बनाने होंगे। अध्यापक, प्रशासकीय अधिकारी, शासन तथा संस्थाचालकों ने भी अपने परंपरागत विचार, व्यवहार तथा कार्यप्रणाली में अमूलाग्र परिवर्तन करना होगा। उच्च शिक्षा के विकास में सबसे ज्यादा अध्यापकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। अतः गुणवत्तापूर्ण अध्यापकों का चयन ग्रामीण उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगा। संसाधनों का अभाव भी ग्रामीण उच्च शिक्षा के विकास में बड़ा अवरोध सिद्ध हो रहा है, जिसके पूर्ति की आवश्यकता है। अंत में कहना गलत नहीं होगा कि सबसे ज्यादा क्षमता च्वजमदजपंस ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों में है। उसे पहचानकर उन्हें वैश्विक स्तर की ज्ञानाधारित शिक्षा तथा कौशल देने का प्रयास करो तो भारत देश निश्चय ही 'सुपर पॉवर' की दिशा में छलॉग लगा सकता है।

प्रस्तावना -

व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्रीय जीवन में उच्च शिक्षा के असाधारण महत्त्व को ध्यान में रखते हुए उस पर गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य को देखते हुए विचारशील तथा कौशलपूर्ण शैक्षिक व्यवस्थापन करने पर उच्च शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास को गति तथा दिशा प्राप्त हो सकती है। उच्च शिक्षा में मुख्यतः महाविद्यालयीन शिक्षा का समावेश होता है। इसमें भी स्थूल रूप में दो भेद हो सकते हैं। 1. पारंपरिक शिक्षा – जिसमें मूलभूत विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, वाणिज्य, भाषाविषयक शिक्षा तथा 2. तंत्रशिक्षा – जिसमें विज्ञान के सहारे मनुष्य का जीवन स्तर बढानेवाला ज्ञान दिया जाता है, जैसे इंजिनियरिंग, मेडिकल, औषध निर्माण शास्त्र आदि का समावेश होता है।

ग्रामीण क्षेत्र में पारंपरिक विद्याशाखाएँ ज्यादा प्रचलित हैं। भविष्य के संकेतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक सजग होने की आवश्यकता है। अध्यापकों की शैक्षिक गुणवत्त का विकास, परिक्षा पद्धतियों में सुधार, स्वायत्त महाविद्यालयों की निर्मिति, विश्वविद्यालय कानून में सुधार जैसे कई मुद्दे हैं जिसके आधार पर उच्च शिक्षा का चित्र भविष्य में कुछ अलग हो सकता है। वैश्विकरण के माहौल को देखते हुए उच्च शिक्षा के सामने खड़ी हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों को आधुनिक संकल्पनाओं को आत्मसात करते हुए उचित कृति कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा। आज की वर्तमान ग्रामीण उच्च शिक्षा विशेशतः पारंपरिक शिक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ कृति कार्यक्रमों पर बल देने की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा : संख्यात्मक वृद्धि –

देश की स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा को लेकर भारतीय राजनीतिक तथा प्रशासकीय घटक उतने गंभीर नहीं थे। किंतु उच्च शिक्षा के महत्त्व को वह ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सके। उसी के परिणामस्वरूप आज उच्च शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। डॉ. सर्जेराव निमसे के अनुसार–''भारतीय उपखंड़ में अंग्रजों ने उच्च शिक्षा की शुरूआत 1857 में मुंबई, मद्रास, कलकत्ता जैसे विश्वविद्यालय स्थापन कर की। उसके पहले बिलकुल कम मात्रा में उच्च शिक्षा की सुविधा थी। सन् 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तब बीस से भी कम विश्वविद्यालय और एक हजार से कम महाविद्यालय, इस देश में उच्च शिक्षा का कार्य कर रहे थे। आज अभिमत विश्वविद्यालय मिलाकर 450 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 20 हजार महाविद्यालय तथा 1 करोड़ 22 लाख से अधिक छात्र विविध विद्याशाखाओं में उच्च शिक्षा ले रहे हैं।''[1] स्पष्ट है कि संख्यात्मक दृष्टि से भारत ने उच्च शिक्षा में पर्याप्त प्रगति की है और भविष्य में भी यह प्रगति बरकरार रहेगी इसमें संदेह नहीं।

गुणात्मक वृद्धि ?

उच्च शिक्षा संस्थाएँ तथा छात्रों की संख्या में पीछले दस–पंद्रह सालों से काफी बढोत्तरी हुई है किंतु संख्यात्मक वृद्धि करने के मोह

Title : *ग्रामीण उच्च शिक्षा : समस्याएँ एवं समाधान*
Source:Indian Streams Research Journal [2230-7850] *अशोक मरळे* **yr:2013 vol:3 iss:2**

में हम उच्च शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि की ओर नजरअंदाज कर रहे हैं यह निश्चय ही भविष्य में विकास की दृष्टि से घातक सिद्ध हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में पारंपरिक शिक्षा जैसे कला, वाणिज्य, विज्ञान जैसी विद्याशाखाएँ शिक्षा का कार्य करते हैं। किंतु उन संस्थाओं की अवस्था काफी निराशाजनक है। इस संदर्भ में नागनाथ कोत्तापल्ले की टिपण्णी काफी मार्मिक हैं। वे कहते हैं –''नई शिक्षा संस्थाएँ सरकारी अनुदान के भरोसे महाविद्यालय निकालते हैं। पहले ऐसी संस्थाओं को हप्तों–हप्तों में अनुदान दिया जाता था। आज नहीं तो कल अनुदान मिलेगा इस विश्वास पर संस्थाचालक महाविद्यालय चलाते थे। अध्यापक भी बिना पारिश्रमिक लिए आधे पेट पढ़ाने का कार्य करते थे। किंतु पीछले कुछ सालों से 'स्थायी रूप से बिना अनुदानित' (Pernanent Non Grantable) तत्त्व पारंपरिक महाविद्यालयों के लिए लागू किया है। इस कारण ऐसे महाविद्यालयों में एम.ए., एम.फिल. हुए छात्र कहीं बिना पारिश्रमिक लिए तो कहीं हजार–पाँच सौ पर पढाने का काम कर रहे हैं। ऐसे अध्यापकों का शिक्षा में मन कैसे लगेगा? वह छात्रों को क्या पढाएँगे और छात्र भी क्या पढेंगे ?ऐसे महाविद्यालयों में पढ़नेवाले छात्र ग्रामीण, दलित, शोशित समाज के हैं। उनके लिए इस तरह के सुविधा न होनेवाले महाविद्यालय हैं। प्रयोगशालाएँ नहीं हैं। ग्रंथालय नहीं हैं। अध्यापकों का वेतन न होने के कारण वे त्रस्त हैं। ऐसे छात्रों को उपाधियाँ तो मिलती हैं किंतु इन उपाधियों का कोई उपयोग नहीं होता है। इस तरीके से उपाधि मिलने के कारण उनमें किसी प्रकार का आत्मविश्वास पैदा नहीं होता है जिसके कारण वे किसी निजी क्षेत्र या खुद के व्यवसाय में खड़े नहीं हो सकते।''2 अतः कहना होगा कि सरकार को 'स्थायी रूप से बिना अनुदानित' जैसे तत्त्व हमेशा के लिए बंद करने होंगे। तभी ग्रामीण क्षेत्र की उच्च शिक्षा में विशेषतः पारंपरिक शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ सकता है।

रोजगाराभिमुख शिक्षा पर बल –

चीन के एक तत्वज्ञ कन्फयुशियस का एक कथन है कि ''नौकरी की अपेक्षा न रखते हुए उच्च का अध्ययन करनेवाला कोई छात्र दिखाई देने की संभावना बिलकुल कम है।''[3] करीब 45 साल पहले इंग्लंड के उच्च शिक्षा का अध्ययन करनेवाले रॉबिन्स आयोग ने अपने रिपोर्ट में यह कथन उद्धृत किया है। कहने का मतलब यह है कि उच्च शिक्षा लेने के पीछे नौकरी यह प्रेरणा और प्रयोजन प्रारंभ से आज तक रहा है।

आज के उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा अगर कोई है तो यह कि इन छात्रों को नौकरी या रोजगार की दृष्टि से तैयार ही नहीं किया जाता। आज उच्च शिक्षा में आनेवाले छात्रों का प्रमाण केवल सात प्रतिशत है जिसपर सभी को दुःख होना स्वाभाविक है। अब यह प्रमाण पंद्रह प्रतिशत तक ले जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। इसके लिए नए महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय खोले जाएँगे। यह एक तरह से अच्छी बात है किंतु सात प्रतिशत में से ही अगर पचास प्रतिशत उच्च शिक्षित रोजगारविहीन है तो यह संख्या पंद्रह प्रतिशत तक जाने के बाद स्थिति क्या होगी इसके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है। आज बी.ए., बी.कॉम., बी.एस्सी. तथा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त छात्र निराश होकर रास्ते पर गर्दन झुकाएँ घुमते हुए दिखाई देते हैं। बी.एड्., एम.फिल., पीएच्.डी. तथा सेट–नेट हुए छात्रों को लाखो रूपए संस्थाओं को दान दिए बगैर नौकरी नहीं मिलती। दलित, गरीब तथा वंचित छात्रों को इस स्थिति का गहरा सामना करना पडता है।

ऐसी स्थिति में सिर्फ उच्च शिक्षा में वृद्धि करने से कुछ नहीं होगा तो छात्र को अपने पैरों पर खड़े होने लायक शिक्षा देने की जरूरत है। स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। विशेशतः वैश्विकरण के युग में स्तरहीन शिक्षा के कारण युवाओं के हाथ में निराशा ही आएगी। इससे बचने के लिए आधुनिक काल में रोजगाराभिमुख शिक्षा के अलावा कोई अन्य पर्याय नहीं है। शासन के स्तर पर तथा पारंपरिक शिक्षा देनेवाली संस्थाओं ने इसके बारे में सचेत होने की सबसे अधिक जरूरत है।

शासन की भूमिका –

उच्च शिक्षा में शासन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है जिसके उचित निर्वाह की आवश्यकता होती है। शासनस्तर पर उदासिनता के कारण सारी शिक्षा संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा से ग्रामीण क्षेत्र के छात्र वंचित रह रहे हैं। साथ ही आर्थिक समस्या से छूटकारा पाने हेतु तथा लोगों का सहभाग बढ़ाने के उद्देश्य से लाया 'बिना अनुदान' (Non Grantable) तत्त्व आज उच्च शिक्षा के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इन संस्थाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं है जिसके कारण यह उच्च शिक्षा व्यवस्था विघातक रूप ले रही है। इस स्थिति पर गंभीरतापूर्वक सोचते हुए शासन को अपनी जिम्मेदारियों से मुँह नहीं फेरना चाहिए। वेतन के लिए पैसे नहीं है इस तरह के बहाने बनाकर अध्यापकों नियुक्ति नहीं हो रही है जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा का स्तर घट रहा है। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में इस समस्या ने गंभीर रूप धारण किया है। यह छवि बदलने के लिए शासन को आर्थिक स्तर पर उच्च शिक्षा को लेकर सतर्क रहना होगा। 11 वीं पंचवार्शिक योजना में केंद्र सरकार ने पर्याप्त राशि का विनियोजन उच्च शिक्षा के लिए किया है। जरूरत है इसमें राज्य शासन के सक्रिय सहभाग की।

समाज के सभी घटकों के लिए अवसर –

उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रगत और स्तरीय शिक्षा के साथ–साथ समाज के सभी घटकों को अवसर मिलने की आवश्यकता है। सदियों मुख्य धारा से वंचित समाजघटकों को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए उच्च शिक्षा जैसा कोई माध्यम नहीं है। सामाजिक तथा आर्थिक दुर्बल घटकों तक उच्च शिक्षा पहुँचने के लिए उच्च शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने की जरूरत है। आज व्यावसायिक शिक्षा का निजीकरण हुआ है जिसका रूप खुले बाजारीकरण ने लिया है जिसके कारण दुर्बलों के लिए यह शिक्षा लेना मुश्किल बन गया है। उस पर तात्काल सामाजिक नियंत्रण लाने की शासन की जिम्मेदारी है।

11 वीं पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत उपेक्षितों की शिक्षा में आनेवाली विविधांगी समस्याओं की ओर सकारात्मक दृष्टि से देखने के निर्देश दिए हैं। आज तक उच्च शिक्षा में समान अवसर प्राप्त न हुए अनेक घटक हैं, वह उपेक्षित न रहे। इसमें महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, घुमंतू जनजाति, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल घटक आदि का समावेश होता है। इनका उच्च शिक्षा के प्रवाह में आना तथा अधिकाधिक उच्चस्तर तक जाना आवश्यक है। वंचितों को प्रोत्साहन के रूप में अनुदान, छात्रवृत्तियॉ देने की योजनाएँ बनानी चाहिए।

11 वीं पंचवार्षिक योजना –

भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के महत्त्व को पहचानकर 11 वीं पंचवार्षिक योजना में उच्च शिक्षा के लिए काफी बडा प्रबंध किया है। ''सॅम पित्रोड़ा की अध्यक्षता में गठित 'राष्टीय ज्ञान आयोग' (National Knowledge Commission) की बहुत सारी सूचनाओं का समावेश 11 वीं पंचवार्षिक योजना में किया है। इस योजना में 2 लाख 70 हजार करोड रूपए की राशि भारत सरकार ने शिक्षा के लिए दी है जिसमें से 87 हजार करोड़ रूपए उच्च शिक्षा के लिए खर्च होगी। 10 वीं पंचवार्षिक योजना की तुलना में यह राशि दस गुणा अधिक है। उच्च शिक्षा में स्तरीय तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु केंद्र सरकार 16 राष्टीय विश्वविद्यालय, 14 अंतर्राष्टीय स्तर के विश्वविद्यालय स्थापन करनेवाले हैं। आज के चार आय.आय.आय.टी. में 11 वीं पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत नए 20 संस्थाओं का समावेश हो रहा है। इसके अलावा N.I.T,2 Artichitcture &Planing, 3 ससेमते की संस्थाएँ जल्द ही स्थापित हो रही है।''[4] इन 80 से ज्यादा नई संस्थाएँ तथा पहले से कार्यरत

बहुत सी अंतर्राष्टीय स्तर की संस्थाऍं मिलकर उच्च शिक्षा में बाढ़ सी आयेगी इसमें संदेह नहीं।

पारंपरिक महाविद्यालयों को कितना लाभ ?

11 वीं पंचवार्षिक योजना के इस सारे चित्र में यह डर भी है कि भारत सरकार की बहुत सारी राशि इन उच्चभ्रु संस्थाओं पर ही अगर खर्च होती है तो राज्य चला रहे प्रचलित विश्वविद्यालयों को कितनी राशि मिलेगी ?सामाजिक न्याय की दृष्टि से तथा आज तक वंचित रहे समाज घटकों तक उचित राशि नहीं पहूँची या पहूँची राशि का सदुपयोग नहीं हुआ तो उच्च शिक्षा के सामने अनेक गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए 11 वीं पंचवार्षिक योजना में राज्य शासन के विचारपूर्ण सहभाग की आवश्यकता है। प्रचलित राज्यस्तरीय विश्वविद्यालयों ने भी अधिक से अधिक राशि अपने विभाग में लाने का प्रयास करना होगा।

विश्वविद्यालय तथा ग्रामीण महाविद्यालय –विचार, व्यवहार तथा कार्यप्रणाली में बदलाव की आवश्यकता –

राज्य स्तर के विश्वविद्यालय, पारंपरिक तथा ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों को भविष्य में विदेशी तथा अभिमत विश्वविद्यालयों का सामना करना है। साथ ही वैश्वीकरण तथा निजीकरण के माहौल को देखते हुए अपने परंपरागत विचार, व्यवहार तथा कार्यप्रणाली में अमूलाग्र परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जैसे–

1. महाविद्यालयों में जानकारी तथा तंत्रज्ञान का इस्तमाल करने के लिए सुयोग्य वातावरण तैयार करना होगा। 'राष्टीय ज्ञान आयोग' (National Knowledge Commission) की शिफारस के अनुसार सभी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय ब्रॉडबॅण्ड कनेक्टिव्हीटी से जोड़ने तथा सभी महाविद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा की आवश्यकता पर बल दिया है जिसका अमल हर संस्था ने करना होगा।
2. अध्यापन पद्धति में परिवर्तन हो। सिर्फ 'जानकारी' पद्धति की शिक्षा देने के बदले उस विषय के ज्ञान के साथ–साथ छात्र का उस विषय में कौशल कैसे विकसित होगा इसके बारे में सोचना होगा।
3. पारंपरिक अध्यापन पद्धति की ओर छात्र आकर्षित नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण छात्रों की अनुपस्थिति की मात्रा बढ रही है। महाविद्यालयों में 'चॅलेंजिंग' तथा बुद्धि को चालना देनेवाली शिक्षा नहीं मिलती। इसके लिए अध्यापन में आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग बड़ी मात्रा में करने की जरूरत है।
4. प्रचलित परीक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता पर बल देना होगा। सत्र परीक्षा, क्रेडिट पद्धति, अंतर्गत परीक्षा, ऑन लाईन परीक्षा आदि उपक्रम शुरू करने चाहिए।
5. समय–समय पर अपने पाठ्यक्रमों में कालानुरूप तथा उपयोगी घटकों के समावेश की आवश्यकता है। आज की प्रचलित विद्याशाखाऍं विशेषतः कला, वाणिज्य तथा विज्ञान शाखा के पाठ्यक्रमों में कुछ मात्रा में व्यावसायिकता लानी होगी।
6. महाविद्यालयों ने रोजगारपरक कार्यक्रमों पर बल देना चाहिए। कुछ छात्र बुद्धिमान होते हुए भी संभाषण जैसी कलाओं में पीछे होते हैं। अतः इन विषयों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन तथा भविष्य में विदेशी सेवाओं के अवसर को देखते हुए विदेशी भाषाओं का ज्ञान दिलाना आदि कृति कार्यक्रम निर्धारित करने चाहिए।
7. अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाऍं आदि के साथ–साथ अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विश्वविद्यालयों में मिलनेवाली साधन सामग्री महाविद्यालयों में भी मिलने के लिए महाविद्यालयों ने प्रयास करने चाहिए। जितना हो सके अध्यापकों के लिए 'शैक्षिक स्वातंत्रय' मिलना चाहिए तभी वे मन से अध्यापन तथा ज्ञान निर्मिति की प्रक्रिया में सहभागी हो सकते हैं।
8. जब तक महाविद्यालयों को स्वायत्तता नहीं मिलती तब तक महाविद्यालय स्वयंपूर्ण नहीं होंगे। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में अपेक्षित विविधता, प्रयोगशीलता प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने के लिए तथा युगानुरूप शिक्षा के लिए स्वायत्तता की जरूरत है।
9. महाविद्यालयों में भ्रष्ट मार्ग से नहीं बल्कि गुणवत्ताधारक अध्यापकों का चयन होना चाहिए। ज्ञानी तथा अच्छे गुणों से युक्त अध्यापकों की शैक्षिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
10. महाविद्यालयों ने ग्रंथालय, प्रयोगशालाऍं आदि आधुनिक सुविधाओं से युक्त कैसी होंगी उस पर ध्यान देना होगा। छात्रों को विविध शैक्षिक साधन उपलब्ध करवाने होंगे। ग्रंथालय में स्तरीय संदर्भ ग्रंथ, क्रमिक पुस्तकें, ज्ञानकोश, विविध विषयों की अनुसंधानात्मक पत्रिकाऍं तथा प्रयोगशालाओं में आवश्यक और पर्याप्त साधन सामग्री उपलब्ध करवानी होगी।
11. छात्र तथा अध्यापकों की शैक्षिक प्रगति हेतु महाविद्यालयों में तज्ञ विद्वानों को आमंत्रित करना चाहिए। इसके लिए व्याख्यानमालाऍं, संमेलन हो।
12. छात्रों के व्यक्तिमत्व विकास हेतु विविध विषयों पर व्याख्यान, चर्चासत्र, विविध प्रतियोगिताऍं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कार शिविर आदि का आयोजन होने की आवश्यकता है।
13. ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों ने भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। शिक्षा के साथ–साथ अन्य उपयोगी आधुनिक कौशल उन्होंने प्राप्त करने चाहिए, जैसे–संगणक का ज्ञान, तंत्रज्ञान की मूलभूत जानकारी, अंग्रेजी संभाजन कौशल आदि।
14. ग्रामीण क्षेत्र के संस्थाचालकों ने भी सेवाभावी वृत्ति से ज्ञानदान को पवित्र कार्य समझकर उच्च शिक्षा की ओर देखना चाहिए।

संदर्भ संकेत –

1.(सं.) प्रा. नागोराव कुभार – 'विचारशलाका' 'त्रैमासिक', अक्तूबर 07 से जून, 08 संयुक्त अंक पृ. 21
2.(सं.) प्रसाद कुलकर्णी – 'प्रबोधन प्रकाशन ज्योति, मासिक पत्रिका, अगस्त, 2008.पृ. 11
3.वही, पृ. 34
4.(सं.) श्री. ग. मुणगेकर – परिवर्तनाचे प्रवाह, सकाळ सुवर्ण महात्सवी प्रकाशन,पुणे, 1982, पृ. 2

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net